आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 24.01.2026 समय : 1905

- आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है।
- निर्वाचन आयोग कल नई दिल्ली में सोलहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएगा।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलापूर्वक समापन।
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज निदेशालय द्वारा अधिकारियों के लिए ई–ऑफिस पोर्टल पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

<><><><><><><>

आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस दिन का उद्देश्य समाज में बालिकाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए जागरुकता फैलाना है। यह दिन समाज को बालिकाओं के लिए समान, सुरक्षित और सशक्त वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे राष्ट्र के विकास में समान रूप से योगदान दे सकें। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार वर्ष 2008 में इस दिन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की वर्षगांठ हाल ही में देश भर में मनाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाए देश की प्रगति का नेतृत्व कर रहीं हैं।

<><><><><><><>

निर्वाचन आयोग कल नई दिल्ली में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है मेरा भारत, मेरा वोट जिसका नारा है 'भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक'। समारोह के दौरान, राष्ट्रपति नव पंजीकृत युवा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान करेंगी। इसके साथ ही वे तकनीक के प्रभावी उपयोग, चुनाव प्रबंधन और मतदाना जागरुकता के लिए विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन प्रथाओं के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में मीडिया के लिए विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहेंगे। समारोह का नेतृत्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे, उनके साथ निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहेंगे।

उधर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। मुख्य समारोह कल सुबह साढ़े दस बजे राजधानी श्री विजयपुरम स्थित टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज के सभागार में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्य सचिव डॉ. चन्द्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की एक सौ तीसवीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों से किया जाएगा। आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा।

<><><><><><><>

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय केंद्र स्थित पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम केंद्र ने मत्स्य निदेशालय और भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के सहयोग से "सतत मत्स्य पालन अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन" विषय पर आयोजित दो–सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। पर्यावरण एवं वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव डॉ. एस. दिनेश कन्नन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे जबकि क्यारी के प्रभारी निदेशक डॉ. जय सुंदर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 जनवरी से आज तक सात रणनीतिक स्थानों—पानीघाट, गुप्तपाड़ा, जंगलीघाट, डिगलीपुर, वांडूर, पोर्ट ब्लेयर और बाराटांग—में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थायी मत्स्य प्रबंधन को मजबूत करना था। गहन तकनीकी व्याख्यानों और व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को अंडमान निकोबार के पारिस्थितिक और सामाजिक–आर्थिक महत्व से अवगत कराया गया। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के नेतृत्व में जंगलीघाट फिशिंग हार्बर पर 'नेविगेशन और सीमैनशिप' तथा भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में 'टूना मत्स्य संसाधनों' पर विशेष प्रदर्शन आयोजित किए गए।

<><><><><><><>

कार्यक्रम में 2050 तक भोजन की मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का मेल को आवश्यक बताया गया तथा निकोबार द्वीप समूह की पारंपरिक संरक्षण रणनीतियों और मौसमी मछली पकड़ने के प्रतिबंधों के महत्व पर भी जोर दिया गया। इससे पहले, अतिरिक्त निदेशक एवं कार्यक्रम समन्वयक, डॉ. सी. शिवपेरुमन ने सभी का स्वागत किया और कार्यक्रम की अवधारणा और लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सतत मछली पकड़ने के तरीकों, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका की सुरक्षा का समर्थन करना है। कार्यक्रम में मछुआरों, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के छात्रों और तटीय सामुदायिक नेताओं सहित कुल 372 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंत में, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

<><><><><><><>

दस दिसम्बर को चौरा द्वीप में होने वाली ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान की तैयारी से संबंधित पब्लिक हियरिंग को मौसम की वजह से टाल दिया गया था, जो अब चार फरवरी को निकोबार जिले के चौरा द्वीप के APWD गेस्ट हाउस होगी।

<><><><><><><>

ग्रामीण विकास और पंचायती राज निदेशालय तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान ज़िले की ग्राम पंचायतों के अधिकारियों के लिए हाल ही में ई–ऑफिस पोर्टल पर दो दिवसीय राज्य–स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपने उद्घाटन भाषण में राज्य नोडल अधिकारी बिजोय कुमार दास ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत पंचायत पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण तथा उनको सशक्त बनाने की भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम में तकनीकी जानकारी को ई–ऑफिस पोर्टल के व्यावहारिक प्रदर्शन के साथ जोड़ा गया तथा प्रतिभागियों को एक सुरक्षित और संरचित डिजिटल वातावरण में डिजिटल फ़ाइल बनाने, नोटिंग और ड्राफ़्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल मूवमेंट और फ़ाइलों के निपटान पर प्रशिक्षित किया गया, जिससे एक पेपरलेस और कुशल कार्यालय इकोसिस्टम बनाने में मदद मिली।

<><><><><><><>

अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखते हुए, दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन, ने कल फरारगंज तहसील के गोविंदापुरम और शोल बे गांवों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अतिक्रमण हटाओ

अभियान के दौरान, सरकारी ज़मीन के साथ–साथ सरकारी सड़कों पर किए गए अतिक्रमणों को राजस्व क्षेत्रीय कर्मचारियों की मदद से हटाया गया। यह अभियान सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से चलाया गया, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को उसके सही इस्तेमाल के लिए बहाल किया जा सके। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के परिणामस्वरूप, लगभग 0.20 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन वापस हासिल की गई और सरकार को सौंप दी गई। इसके अलावा, सरकारी सड़क पर सभी रुकावटों को पूरी तरह से हटा दिया गया, जिससे लोगों की आवाजाही आसान और सुरक्षित हो गई।

<><><><><><><>